अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबकी इजाजत लेना बंद कर दीजिए।
– अज्ञात

रोजी–रोटी का संकट

प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश से लौटने पर 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। इस बारे में पिछले दिनों केंद्र और राज्यों में विस्तृत चर्चा हुई थी और राज्यों ने विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना शुरू कर दिया था।

रविंद्र जैन।

खाड़ी देशों में रह रहे लगभग एक करोड़ भारतीयों के सामने रोजी–रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब वे अपने देश लौटना चाहते हैं। भारत सरकार ने भी उन्हें वापस लाने का मन बना लिया है। संयुक्त अरब अमीरात में डेढ़ लाख से ज्यादा भारतीयों ने घर लौटने के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के तहत भारतीय मिशनों में आवेदन दिया है।

लॉकडाउन के कारण वहां फंसे तथा घर लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पिछले सप्ताह शुरू की गई थी। यूएई में भारत के महा वाणिज्यदूत के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन शनिवार की शाम छह बजे तक ही प्राप्त हो चुके थे।

इन डेढ़ लाख आवेदनों में से एक चौथाई ऐसे लोगों के हैं जो अपनी नौकरी गंवाने के बाद स्वदेश लौटना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले करीब 40 फीसदी आवेदक श्रमिक हैं जबकि 20 प्रतिशत प्रफेशनल्स हैं। इनमें से 55 फीसदी अकेले केरल से हैं, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रदेशों के श्रमिक भी रजिस्ट्री कराएंगे। वैसे करीब 10 फीसदी आवेदन पर्यटकों के भी हैं, जो भारत में जारी लॉकडाउन के कारण वहां फंस गए हैं।

ईरान और अन्य खाड़ी देशों में फंसे छात्रों, कामगारों, मजदूरों और मछुआरों को भी वहां से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। गौर से देखें तो खाड़ी देशों में इतनी बड़ी तादाद में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें महज कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी हैं। वहां उनकी जीविका मुख्यतः तेल बाजार से निकलती है, जो साल की शुरुआत से ही मार खा रहा है। इससे इस क्षेत्र की संपदा कम हुई है और कई कंपनियों के बंद होने की नौबत आ गई है।

भारतीय श्रमिकों की एक बड़ी संख्या कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कार्यरत रही है जो बिल्कुल ठप पड़ा है। उनकी बेरोजगारी का असर भारत भेजी जाने वाली उनकी 50 अरब डॉलर कमाई पर भी पड़ेगा, जो भारत के लिए बड़ा झटका है। बहरहाल, भारतीयों को वहां अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें लाने के लिए खाड़ी के क्षेत्र में नौसेना और वायुसेना को अपने युद्धपोतों और विमानों को स्टैंडबाय में रखने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पिछले दिनों कहा कि हमने अपने पोत तैयार कर लिए हैं और जैसे ही भारतीय कामगारों को निकालने के आदेश मिलते हैं, हम निकल पड़ेंगे।

प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश से लौटने पर 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। इस बारे में पिछले दिनों केंद्र और राज्यों में विस्तृत चर्चा हुई थी और राज्यों ने विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना शुरू कर दिया था। फैसला यही था कि लॉकडाउन खुलने के बाद युद्ध–स्तर पर भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान चलाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिए जाने के बाद इस अभियान की शुरुआत कब होगी, कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करें कि खाड़ी में फंसे सभी भारतीयों की घर वापसी जल्द ही संभव हो सकेगी।

परित्याग

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

यक्षप्रश्न उपस्थित है कि जिस ज्येष्ठ को वे निष्कलुष स्नेह करते हैं, जिसके लिए वो समस्त संसार का परित्याग सहर्ष कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें तत्क्षण प्राण त्यागने में किंचित मात्र विलंब नहीं हो सकता, उन श्रीराम के समक्ष उनका प्रेम कैसे प्रमाणित होगा। स्तब्ध, अश्रुपूरित नेत्रों के साथ महाराज कैकेयी से अन्य वरों की मांग की करुण गुहार लगा बैठते हैं। हतभागी महाराज! कहां जानते थे कि उन्हें रघुकुल की मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों से बढ़कर प्रिय पुत्र का परित्याग करना पड़ जाएगा। जिस दिन हम अपनी कद्र करना सीख जाते हैं, ईश्वर हम पर मेहरबान होने लगता है। बच्चों के लिए पैसा जमा करके छोड़ जाने की बजाय उन्हें धन कमाने की विद्या सिखाएं।

संपादकीय

पहली प्रथमिकता

लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण के मूल्यों पर आधारित सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने ही लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी ली। हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलजी, सीआईएसआर, आईआईटी तथा एम्स जैसे संस्थानों ने अपनी उपयोगिता फिर से सिद्ध की है। प्रसिद्ध विचारक नोम चॉम्स्की ने कहा भी कि कोरोना वायरस का निदान इसलिए नहीं खोजा जा सका कि कंपनियों की सुंदर बनाने वाले क्रीम में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनका कहना है कि जरूरी वैक्सीनों पर होने वाले शोध सरकारी पैसों से ही होते रहे हैं। संपन्न देशों में मची अफरातफरी और बड़ी संख्या में मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से सार्वजनिक क्षेत्र में ही चलाने की मांग तेज कर दी है।

कोरोना ने बता दिया है कि दुनिया को बंधुत्व, समानता तथा लोकतंत्र के ऊंचे मानवीय मूल्यों की ओर ले जाने में अभी की विश्व–व्यवस्था सक्षम नहीं है। इसके सुधरने के आसार भी नहीं हैं बल्कि कोरोना के बाद की दुनिया के अधिक बंटी होने तथा संकीर्ण होने का खतरा है। वायरस के प्रसार को लेकर अमेरिका व चीन के बीच का विवाद, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए दोनों के बीच चल रहे अघोषित युद्ध और यूरोपीय देशों के बीच एक–दूसरे के खिलाफ नाराजगी आगे के नफरत भरे माहौल के ही संकेत हैं। बाजारों को फिर से खड़ा करने और उसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए संपन्न देशों के बीच तीखी लड़ाई होने वाली है। नफरत सिर्फ देशों के बीच सीमित नहीं रहेगी। यह समुदायों के बीच भी पनप रही है।

तो कुछ लोग संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित दुनिया की भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसमें तानाशाही का बोलबाला होगा और लोकतांत्रिक अधिकारों में कमी रहेगी।

कठघरे में सभ्यता

अनिल सिन्हा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और दुनिया के कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस की महामारी जल्द जाने वाली नहीं है। उनका यह भी कहना है कि इसके थम जाने के बाद भी हमें बदले तरीके से ही जीना होगा। दूसरी ओर, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिशास्त्री कोराना के बाद की दुनिया के बारे में तरह–तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कई आशावादी लोग नजदीक भविष्य में ज्यादा समझ और सहयोग वाली दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं तो कुछ लोग संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित दुनिया की भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसमें तानाशाही का बोलबाला होगा और लोकतांत्रिक अधिकारों में कमी रहेगी।

सच तो यह है कि कोरोना के प्रकोप ने भूमंडलीकरण वाली अर्थव्यवस्था और उच्च तकनीक पर आधारित हमारी वर्तमान सभ्यता को सवालों के घेरे में ला दिया है। ग्लोबलाइजेशन ने विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ा है, लेकिन कोरोना ने साबित कर दिया है कि यह एकता आपसी सहयोग की बुनियाद पर नहीं है। महामारी की शुरुआत में लगा था कि मानव समुदाय पर आए इतिहास के सबसे बड़े खतरे के खिलाफ पूरी दुनिया साथ मिल कर खड़ी हो जाएगी और

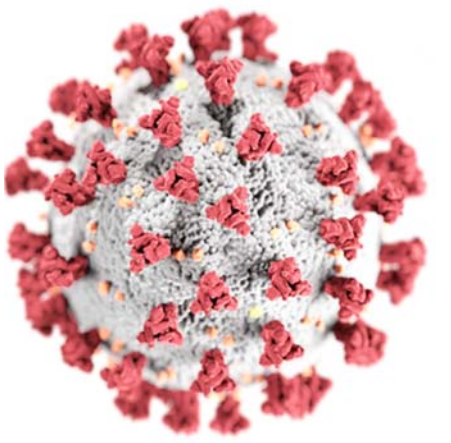

धरती के किसी हिस्से का संसाधन पूरे मानव–हित के काम आएगा। लेकिन जल्द ही यह भ्रम मिट गया। कोरोना की भयानक मार झेल रहा इटली यूरोपीय यूनियन के व्यवहार से दुखी है और इसमें बने रहने पर फिर से विचार कर रहा है। यूनियन से जुड़े ग्रीस और पुर्तगाल जैसे देशों की संपन्न जर्मनी ने कोई मदद नहीं की जबकि क्यूबा उनकी मदद के लिए आगे आया। जब एकीकृत यूरोपीय संघ के देशों का यह हाल है तो सूडान या यमन जैसे मुल्कों की सहायता कैसे होगी? वे तो युद्ध, अकाल और घोर गरीबी के कारण मानवीय जीवन की कल्पना करना ही छोड़ चुके हैं। भारत जैसा मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश भी कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह सामने है।

पूरी दुनिया मिलकर लड़ेगी' के नारों के बीच टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर्स तथा दवाइयों के बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच ले जाने में अमेरिका ने कोई संकोच नहीं दिखाया। भारत से ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मंगा लेने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी वाले बयान को कैसे भूला जा सकता है? यही नहीं, अमेरिका ने ईरान, वेनिजुएला तथा निकारागुआ जैसे देशों को भी मेडिकल सहायता पाने के लिए उनके खिलाफ प्रतिबंध में कोई छूट नहीं दी। भले ही वेंटिलेटर्स की कमी हो, उसने अपने सैनिक अभियान स्थगित नहीं किए। कोरोना की वजह से कहीं भी सैनिक–तनावों के घटने की खबर नहीं है। इसमें भारत–पाकिस्तान की सीमा पर तनाव भी शामिल है।

इन सबके बीच आम लोगों का व्यवहार उम्मीद पैदा करने वाला है। डॉक्टरों और नर्सों ने अपना जीवन जोखिम में डाल कर लोगों के प्राण बचाने की कोशिश की है। भारत जैसे मुल्क में कोरोना संक्रमण से बचाने वाली पोशाक और दूसरी चीजों की कमी की परवाह न करते हुए लोग इस काम में जुटे हैं। भुखमरी झेल रहे लोगों को राशन तथा भोजन पहुंचाने में स्थानीय स्तर के स्वतःस्फूर्त प्रयास प्रेरणादायक हैं। उदारीकरण के दौर में बनी व्यवस्था खोखली साबित हुई है।

अष्टयोग-5049

	3		4	5		
2	30	7	31		34	2
1			3		7	
	28	6	31	6	39	3
4		1			5	7
3	30		32	7	34	
	5		6		2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5048 का हल

2	3	6	4	1	7	5
7	30	2	25	2	34	4
4	5	1	3	6	7	2
6	28	5	35	3	39	6
1	2	4	6	7	5	3
5	30	3	42	5	34	7
3	5	7	6	4	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

प्लेग का इतिहास

मोहन। क्या प्लेग के इतिहास से हम कुछ सीख नहीं सकते? पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य में आई ब्लैक डेथ की बीमारी ने यूरोपीय पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई। बीमारी के बाद कम हो गई आबादी ने ऐसे सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाए जिसने यूरोप को दासप्रथा और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई। उसके सोचने–समझने के तरीके को वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक बनाया। क्या हम जलवायु परिवर्तन तथा परमाणु युद्ध के खतरे के सामने खड़े विश्व को बचाने के लिए एक मानवीय अर्थव्यवस्था की ओर नहीं बढ़ सकते जो प्रकृति के बेहिसाब दोहन पर आधारित न हो और मौज करो की जगह आपसी सहयोग वाले सादे जीवन के विचार की ओर ले जाए? कोरोना पर काबू पाने के बहाने अल्पसंख्यकों तथा दबे लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। कुछ देशों में लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की प्रक्रिया भी चल रही है । हंगरी में तो चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग के बहाने लोगों की आवाज दबाई जा रही है।